अध्याय–20

तकनीकी संस्थान (इस्पात मंत्रालय के अधीन)

बीजू पटनायक राष्ट्रीय स्टील इन्स्टीट्यूट

इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित टास्क फोर्स के विकसित सिद्धांत के आधार पर पुरी में एक राष्ट्रीय इस्पात इन्स्टीट्यूट वरन् प्रशिक्षण सह आर एंड डी केन्द की स्थापना करने का निर्णय संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लिया गया। इस्पात मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी, 2001 को पुरी में बीजू पटनायक राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट कार्य करना शुरू किया। संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष ही बीपीएनएसएल के अध्यक्ष होते हैं। इस्पात उद्योग के बदलते परिपेक्ष को देखते हुए घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। इस समय बीपीएनएसआई वैल्डिंग प्रौद्यौगिकी साफ्टवेयर विकास तथा कम्प्यूटर अनुरक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम का आयोजन कर रही है। जेपीसी के फंड से कैबिनेट द्वारा 20 फरवरी, 2004 को 10 करोड़ रूपये की अग्रिम राशि बीपीएनएसआई को आत्मनिर्भर बनने के लिए दिया गया।

वर्ष 2004–05 के दौरान बीपीएनएसआई द्वारा किए गए मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

(i) बीपीएनएसआई ने 8–9 अप्रैल 2004 तक स्टैनलैस स्टील फैबरीकेशन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। जिसमें देश के सभी भागों कें प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इससे इस संस्थान को विभिन्न उद्योगों से सीधे संबंध स्थापित करने में सहायता मिली है जिससे वह अपने व्यवसायिक कार्यों को निष्पादन करने में सक्षम होंगे।

(ii) विभिन्न इंजीनियरिंग कालेज के 47 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया।

(iii) मैसर्स कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट ने बीपीएनएसआई को भुवनेश्वर में अनुसंधान एवं विकास कार्यों के निष्पादन के लिए 2500–4000 वर्ग फुट क्षेत्र प्रदान किया। जिस पर कोई वित्तीय देयता नहीं होगी।

(iv) मैसर्स मेसीजेन इंडो आस्ट्रेलियन वेन्चर (प्रा.) लि. टिटलागद (उड़ीसा) ने अपनी इकाई जो एक लघु इस्पात संयंत्र है, को बीपीएनएसआई को ऐसे आर एंड डी कार्यकलापों के लिए डमी संयंत्र के रूप में उपयोग करने के लिए देने की पेशकश की है, जिससे इस्पात क्षेत्र में एसएमई से संबंधित नई प्रौद्योगिकी का विकास हो सके।

राष्ट्रीय द्वितीयक इस्पात तकनीकी संस्थान

1984 में इस संस्था की स्थापना का विचार आया। 18 अगस्त 1981 को इसे सोसाइटी के रूप में शामिल कर लिया गया, जिसका निबंधित कार्यालय चंडीगढ़ में है (लौह और इस्पात विकास आयुक्त की अध्यक्षता में)। इसके अधोलिखित लक्ष्य ओर उद्देश्य है– द्वितीयक इस्पात संयंत्र को प्रशिक्षित मानव–शक्ति उपलब्ध कराना (अल्पावधि और दीर्घावधि पाठ्यक्रम आयोजित करने)

- उच्च तकनीक के बारे में सेमीनार, संगोष्ठी, कार्यशालाओं ओर इन गृह प्रशिक्षण कार्यक्रमों जो द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लिए प्रासंगिक हो को आयोजित करके।
- विभिन्न औद्योगिक सेवाएं और जाँच सुविधाएं मुहैया कराना
- कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान करना, तकनीकी समस्याओं के निराकरण, ऊर्जा क्षमता बढ़ाना और प्रदूषण स्तर घटाने के संदर्भ में
- सीमा क्षेत्रों में इस क्षेत्र के अद्यतन तकनीक के बारे में अनुसंधान, विकास और डिजाइन कार्य की जानकारी देना
- उद्योग के बारे में ब्यौरा और सूचना पुनर्प्राप्ति की व्यवस्था करना।
- उद्योग और शैक्षिणिक साल ही अनुसंधान संस्थान के बीच आपसी सम्पर्क के लिए एक मंच प्रदान करना।

मीडियम मर्चेंट और स्ट्रक्चरल मिल

अधोलिखित द्वितीयक इस्पात क्षेत्र जो संस्थान के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है:–

- इलेक्ट्रिक आर्क और इंडक्शन फर्नेस यूनिट्स
- लैड्ल रिफाइनिंग सुविधाएं
- रॉलिंग मिल्स (हॉट एण्ड कोल्ड)
- डायरेक्ट रिड्यूसड ऑयरन यूनिट्स

संस्थान का अपना कैम्पस जो जीटी रोड पर 6 एकड़ भूमि पर बना है– मंडी गोविंदगढ़, पंजाब। प्रयोगशाला और पुस्तकालय के अतिरिक्त संस्थान में छात्रावास और कर्मचारी आवास की सुविधाएं हैं इसके दो क्षेत्रिय केन्द्र नागपुर और कोलकाता में अवस्थित हैं संस्थान का मुख्यालय अप्रैल 1997 में दिल्ली से मंडी गोविंदगढ़ चला गया।

संस्थान का प्रबंधन बोर्ड ऑफ गर्वनरों के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य उद्योग, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संगठनों और इस्पात मंत्रालय से आते हैं। इस्पात मंत्रालय का संयुक्त सचिव डी सी आई एण्ड एस देखभाल करता है और संस्थान का अध्यक्ष होता है।

इस्पात विकास और वृद्धि संस्थाना (INSDAG)

इस्पात उत्पादकों को पहल से इस संस्थान की स्थापना हुई ओर यह 26 अगस्त 1996 को एक सोसाइटी के रूप में निबंधित हुआ। संस्थान का मिशन सभी हिस्सेदारों के साथ मिलकर कार्य करना है ताकि वेतन और इस्पात का प्रभावी इस्तेमाल का विकास हो और उपभोक्ताओं को पर्याप्त मूल्य उपलबध हो।

संस्थान मुख्य तौर पर इस्पात प्रयोक्ता में तकनीक और इस्पात उपभोक्ताओं के लिए बाजार का विकास करता है। संस्था जॉयंट प्लांट कमेटी (JPC) कलकत्ता के एक हिस्से में अवस्थित है। INSDAG से उम्मीद की गई थी। यह उद्योग के अंशदान से कार्य करेगा और वृद्धि दर्ज करेगा। हालांकि सदस्य अंशदान कुल वित्त जरूरत का मात्र 20 प्रतिशत ही है। बाकी का हिस्सा JPC के के अनुदान से पूरा किया जाता है।